



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 आश्विन 1944 (श10)  
(सं0 पटना 885) पटना, वृहस्पतिवार, 20 अक्टूबर 2022

---

सं० 08/नि०था०-11-02/2019 सा०प्र०-17500  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
23 सितम्बर 2022

श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1104/11 (1341/08), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, रहुई (नालन्दा) के विरुद्ध इंदिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितता बरतने एवं उक्त मामले में निगरानी थाना कांड संख्या-030/2008 दिनांक 29.05.2008 दर्ज होने तथा श्री कुमार को नामजद अभियुक्त बनाये जाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6691 दिनांक 19.06.08 द्वारा श्री कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-4850 दिनांक 16.10.09 द्वारा श्री संजय कुमार, बि.प्र.से., कोटि क्रमांक-1104/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’, श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा से श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4287 दिनांक 21.03.12 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध मुख्य रूप से यह आरोप है कि उनके द्वारा रहुई प्रखण्ड के हवनपुरा पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 38 लाभुकों के खाता खोलवाने में अनियमितता बरती गयी। लाभुकों की अनुपस्थिति तथा बिना उनका फोटो तथा आवश्यक कागजात प्राप्त किये मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, निजाय के द्वारा खाता खोला गया। खाता खोलवाने में संबंधित कर्मियों द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा खाता खोलने में अनियमितता बरती गयी।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जॉच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-449 दिनांक 07.06.12 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा व्यक्त की गयी असहमति तथा असहमति के बिन्दु पर श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16477 दिनांक 04.12.12 द्वारा निलम्बन मुक्त करते हुए 'निन्दन (वर्ष 2007-08) एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड संसूचित किया गया। साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4052 दिनांक 11.03.13 द्वारा श्री कुमार के निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने तथा उक्त अवधि के पेंशन प्रयोजनार्थ सेवा में गणना किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा दायर पुनर्विलोकन अर्जी को समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7088 दिनांक 03.05.13 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC सं0-11369/14 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.19 को आदेश पारित करते हुए दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16477 दिनांक 04.12.12 तथा पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7088 दिनांक 03.05.13 को निरस्त (Quashed) कर दिया गया।

न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"13. In view of such procedural irregularity, the consequential findings of the Disciplinary Authority based on such illegal and unfair procedure is unsustainable. In this connection, this Court would only reiterate the law as laid down by the Apex Court in the case of Punjab National Bank and Others-Versus-Kunj Behari Misra, (1998) 7 Supreme Court Cases 84. The punishment imposed by the Disciplinary Authority under communication dated 04.12.2012 being outcome of a procedure in violation of Rule 18 of Bihar CCA Rules, 2005 as also the law in this regard in the case of Kunj Behari Misra (supra) is, therefore, quashed.

14. In view of quashing of the order of punishment, the consequential order issued by the Joint Secretary (respondent No 3) reiterating the illegal order of the Disciplinary Authority and without considering the illegal procedure adopted by the Disciplinary Authority and communicating rejection of petitioner's appeal under Letter dated 03.05.2013 bearing Memo No.-7088 are also unsustainable and are hereby quashed.

15. The writ petition is allowed.

16. As a result of quashing of the impugned order, the petitioner would be entitled to all consequential benefits.

17. However, this order would not preclude the respondent-authorities from proceeding against the petitioner by following the procedure prescribed under Bihar CCA Rules, and in accordance with law."

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध LPA दायर करने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श में अंकित किया गया कि उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि CWJC में मा0 Single Judge द्वारा पारित न्यायादेश के विरुद्ध LPA में सफल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वादी को दिया गया दंड minor nature (लघु दंड) का है और यदि State चाहे तो नियमानुसार Fresh कार्यवाही का निर्णय भी ले सकता है।

विधि विभाग का परामर्श निम्नवत् है :-

"In my opinion, the findings recorded by the Hon'ble High Court cannot be faulted to the extent that the letter no. 972 dated 13.02.2012 of the District Magistrate, Nalanda was nowhere discussed by the Inquiry Officer in his inquiry report. If this letter was not part of the departmental proceeding, then the same could not have been based for recording difference. However, the Presenting Officer did bring on record D.D.C. letter no. 3234 dated 12.12.2011 and D.M. letter no. 784 dated 04.02.2012. If these two documents are

substantially same and similar as that of letter no.972 dated 13.02.2012 of the D.M. Nalanda then a point can be raised that no substantial prejudice is caused to the delinquent. However, the grounds of appeal prepared as draft and kept at page-1175-1173/C, does not suggest the same. Under the given facts, there is very little scope of success if the state proposes to go in appeal against the Single Judge order. The penalty imposed is minor in nature and liberty is already given to continue the proceeding afresh against the delinquent, if desired by the state in accordance with law."

CWJC No-11369/14 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.19 को पारित आदेश एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6288 दिनांक 29.06.20 द्वारा श्री कुमार को संसूचित दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16477 दिनांक 04.12.12 तथा पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7088 दिनांक 03.05.13 को वापस लिया गया एवं श्री कुमार के विरुद्ध Fresh कार्यवाही हेतु नये प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। साथ ही अनुमोदित आरोप पत्र के साथ विभागीय पत्रांक-6945 दिनांक 07.08.20 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके क्रम में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 05.03.2022 एवं 29.03.2022) समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध अपने कर्तव्य/दायित्व का निर्वहन नहीं करने संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9545 दिनांक 13.06.2022 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया:-

(i)निन्दन (वर्ष 2007-08)

तदुपरान्त श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन(पत्रांक-726/CON/IGIMS दिनांक 10.08.2022) समर्पित करते हुए सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-11369/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 19.06.2008 से दिनांक 03.12.2012 तक के निलंबन अवधि के बकाया वेतनादि भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1104/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, रहुई (नालन्दा) सम्प्रति प्रशासी पदाधिकारी, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के निलंबन अवधि (दिनांक 19.06.2008 से दिनांक 03.12.2012 तक) का पूर्ण वेतनादि भुगतान करने एवं उक्त अवधि को सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि के रूप में मानते हुए विनियमित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 885-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>